अमेरिकी चुनाव और भारतीय लोकतंत्र

दोनों खतरे में

अमेरिका में 3 नवम्बर को सम्पन्न हुये राष्ट्रपति पद के चुनाव का अन्तिम फैसला होना हालांकि अभी बाकी है लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडन को मिले अभूतपूर्व मतों ने बता दिया कि अमेरिकनों ने ट्रम्प की राजनीति को नकार दिया है। जो बाईडन को 7 करोड़ से ज्यादा मत मिले हैं जो आज तक किसी भी राष्ट्रपति को मिले मतो में सर्वाधिक है। हालांकि मतदाताओं का बहुमत स्पष्ट रूप से जो बाईडन को मिल चुका है लेकिन बड़े ही उलझे हुए चुनावी नियमों के कारण वो अभी भी हार सकते हैं इसी कारण उनकी पार्टी की हिलेरी क्लिंटन 2016 के चुनाव में ट्रम्प से 30 लाख मत ज्यादा मिलने के बावजूद चुनाव हार गयी थी।

बता दे कि अमेरिका में राष्ट्रपति न तो सीधे मतदाताओं द्वारा चुना जाता है और न भारत की तरह संसद सदस्यों द्वारा। वहां के मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो आगे राष्ट्रपति चुनते हैं। ज्यादातर राज्यों में 'विनर टेक्स आल' नियम लागू है यानि जिस पार्टी को बहुमत मिल गया सारी सीटें उसी की। जैसे कि केलिफोर्निया राज्य से 55 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो राज्य के सभी डाले गये मतो का अधिकतम जिसे मिलेगा उसे ही ये सारी सीटें मिलेगी। सीधा सा मतलब है कि या तो आप को वहां से 55 सीटें मिलेंगी या फिर जीरो। या तो बाबा रेल में या फिर जेल में। बहुमत वाला भी हार सकता है और अल्पमत वाला भी जीत सकता है।

दूसरा नियम ये है कि मतदान का दिन तो निश्चित है लेकिन आप उससे पहले डाक द्वारा अपना मत भेज सकते हैं। मजे की बात तो ये है कि आपका मत अगर मतदान दिवस के बाद भी पहुंचा तो भी स्वीकार कर लिया जायेगा बशर्ते कि उस पर डाकखाने की मुहर उससे पहले की हो। कई राज्यों में तो तीन दिन बाद तक प्राप्त होने वाले मतों को भी गिना जाता है। इससे चुनाव परिणाम में देरी होना स्वभाविक है। अबकी बार सर्वाधिक लगभग 10 करोड़ मतदाताओं ने डाक मतपत्रों का प्रयोग किया है जो इन चुनावों में उनकी रूचि और चिन्ता को दिखाता है।

अमेरिका के वर्तमान चुनाव के तीन पहलू भारतीय चुनावों की तुलना में गौर करने लायक है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो यह है कि ट्रम्प को सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में बढ़त हासिल हुई है। गौरतलब है कि ट्रम्प अपने चुनाव प्रचार में गोरों की प्रभुता के पक्ष में खड़े रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जहां गोरों की बहुतायत है और शिक्षित कम है, वहां उनको ज्यादा वोट मिलना ये दिखाता है कि कम पढ़े लिखे लोगों ने उनके नस्लवादी रवैये को स्वीकारा है। यानी नस्ल के आधार पर भेदभाव को सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही कम पढ़े लिखों के बीच ट्रम्प फैला पाये। इसके बरक्स भारत में मोदी और संघ, धार्मिक और जातीय आधार पर भेदभाव को व्यापक पैमाने पर पढ़े लिखे और ग्रामीण शहरी सभी के बीच फैला पाये हैं। इसी के फलस्वरूप भयंकर बेरोजगारी और भुखमरी के बावजूद मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आयी है। विशेषकर उच्च मध्यम वर्ग अभी भी उनके साथ खड़ा है। इनमें शिक्षित और उच्च नौकरीपरेशा लोग बड़ी संख्या में शामिल है।

दूसरा पहलू ये है कि ट्रम्प अपनी कोशिशों के बावजूद महत्वपूर्ण राज्य संस्थाओं को भ्रष्ट और पक्षपाती नहीं बना पाये हैं। वहां के स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न मुखिया, पुलिस और फौजों के प्रमुख, जज, सभी कभी न कभी ट्रम्प के असंवैधानिक कार्यो के खिलाफ खड़े नजर आये हैं, जिसे कोविड संक्रमण की लड़ाई में और 'ब्लैक लाइव्स मैटर' आंदोलन में स्पष्ट देखा जा सकता है। कालों के आंदोलन में न सिर्फ गोरों लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि पुलिस और फौज के प्रमुखों ने बिल्कुल स्पष्ट बयान दिया कि वो संविधान की पालना के लिये हैं और वो ट्रम्प के अंसवैधानिक आदेशों को लागू नहीं करेंगे। इसके विपरीत भारत में सभी प्रमुख राज्य संस्थाएं मोदी के सामने घुटने टेक चुकी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और बोबड़े, सेनाध्यक्षों, रिजर्व बैंक व अन्य संस्थाओं के कार्यो व निर्णयों में इसे साफ देखा जा सकता है। यह दिखाता है कि अमेरिकी दिमागों और संस्थाओं में न्याय और समानता के सिद्धान्त कितने सुस्थापित है।

तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पूंजीवाद के गढ़ अमेरिका में पूंजीपतियों ने किसी सरकार या पार्टी के सामने समर्पण नहीं किया है। जबकि भारत में हर क्षेत्र में अम्बानी और अडानी को ठेके मिलने के बावजूद दूसरे पूंजीपति चुप है। यह भारत में क्रोनी केपिटलिज्म यानी सरकार के तलहड्ड पूंजीवाद का उदाहारण है। शुद्ध पूंजीवाद एक इमानदार और पारदर्शी शासन की मांग करता है जबकि तलहड्ड पूंजीवाद भ्रष्ट और गोपनीय तरीके से काम करना चाहता हे, जिसके लिये निरकुंश तानाशाही सबसे ज्यादा रास आती है। पूंजीवाद सिर्फ नीति निर्धारण में भ्रष्टाचार चाहता है उन्हें लागू करने में नहीं।

भारत और अमेरिका का हालिया चुनावों और उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है किअमेरिका में शुद्ध पूंजीवाद का गढ़ होते हुए भी जनतांत्रिक मूल्य वहां की संस्कृति और संस्थाओं में स्थापित हो गये हैं जबकि भारत के तलहड्ड पूंजीवाद की जरूरत एक भ्रष्ट और निरकुंश तानाशाही है। इसलिये जहां अमेरिका में पूंजीवादी जनतंत्र का झंडा बुलन्द रहेगा वहीं भारत में हिंसा और गृहयुद्ध की तरफ बढ़ने से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि भ्रष्ट तानाशाहियां अन्तत: वहीं ले जाती है और जिनके पास एक मजबूत फासिस्ट संगठन हो उनका तो इसऔर बढ़ना लाजमी है।

अजातशत्रु

खबर की पोल खोल

-ज्योति गोयल

मंदिर के नाम पर किया गुमराह

सोशल मीडिया के दौर में पुरानी, झूठी, सम्पादित विडियोज़ और तस्वीरों से अक्सर लोग गुमराह हो जाते है। हाल ही में दो तस्वीरें वायरल हुई है जिन्हें अयोध्या राम मन्दिर के निर्माण की तस्वीरें बताकर फैलाया जा रहा था। सूत्रों (Alt news) से पता लगा है कि ये तस्वीरें राम मन्दिर की नहीं है। असल में ये तस्वीरें वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना की है।

कॉरिडोर का निर्माण मार्च 2019 में शुरू हुआ था और अगस्त 2021 इसको समाप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। ये तस्वीरें हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी थी 30 अक्टूबर की तारीख को और दैनिक जागरण में 27 अक्टूबर को।

राम मन्दिर के नाम से इन तस्वीरों को फैलाने वालों में साध्वी प्रिया मिश्रा और गौमाता गऊ सेवा ट्रस्ट शामिल है।

चोट अर्णब को लगी....

पेज दो का शेष

पिलाते रहे और लगातार पुलिस के साथ न जाने पर अड़े रहे। कभी सास-ससुर से मिलने का बहाना तो कभी पत्नी से बात करने की बात कहकर समय जाया करते रहे। और किसी भी कीमत पर कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे।

इस बीच, लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए वह लगातार खुद के ऊपर हमले और अपने बीवी और बेटे के साथ हाथापाई का पुलिस पर आरोप लगाते रहे। जबकि किसी भी वीडियो में यह बात नहीं दिखी और न ही उसका कोई दूसरा साक्ष्य सामने आया है। अब अर्णब को डिफेंड करने वालों को ज़रूर यह बात बतानी चाहिए कि आखिर पुलिस को वहां कितना इंतजार करना चाहिए था? और अर्णब को ले जाने के लिए उसे क्या करना चाहिए था? आखिर में पुलिस ने उनकी बांह पकड़ कर और पूरे सलीके से उन्हें पुलिस वैन तक ले गयी। और अब बाद में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है।

अर्णब की गिरफ्तारी के बाद सत्ता के खेमे से जो प्रतिक्रिया आयी है वह अभूतपूर्व है। कैबिनेट मंत्री से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री और संघ के आला नेताओं ने इस तरह से प्रतिक्रिया दी हैं मानो उन्हें ऐसा करने के लिए ऊपर से निर्देश दिए गए हों। सब ने एक सुर में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। और मुंबई पुलिस के कदम को फासिस्ट बताया है। यूपी के सीएम योगी तक ने इसका प्रतिकार किया है। और इसे प्रेस पर हमला बताया है। जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही हाथरस में चार दिनों तक पत्रकारों को गांव में घुसने नहीं दिया। घटना को कवर करने जा रहे केरल के एक पत्रकार को रास्ते से उठाकर यूएपीए जैसे काले कानून के तहत जेल मे डलवा दिया।

कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया को दो-दो बार उठवा

लिया था। मिर्जापुर के एक पत्रकार के खिलाफ सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज करवा दिया क्योंकि उसने मिडडे मील में मिलावट और भ्रष्टाचार के मामले को उठाया था। उनको भी अर्णब की गिरफ्तारी का दर्द हुआ है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस चिड़िया का नाम है इस घटना के बाद ही पता चला है। राजनाथ सिंह से लेकर प्रकाश जावड़ेकर और शिवराज चौहान से लेकर स्मृति ईरानी तक ने प्रतिक्रिया देने में कोई देरी नहीं लगायी। इनसे ज़रूर यह बात पूछी जानी चाहिए कि गौरी लंकेश क्या पत्रकार नहीं थीं? या फिर उनको बोलने की आज़ादी का अधिकार हासिल नहीं था? उनकी दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी।

क्या किसी कैबिनेट मंत्री ने उनकी हत्या की निंदा की? उनके हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए किसी ने बयान जारी किया? देश के इतने सारे बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कर्मी निरपराध, निर्दोष जेल की सींखचों के भीतर महीनों और सालों से कैद हैं लेकिन उनको लेकर संघी प्रवक्ता राकेश कुमार सिन्हा को फासीवाद की याद नहीं आयी और अब जबकि अर्णब की गिरफ्तारी हुई है तो उन्हें फासीवाद का खतरा सता रहा है। और आज वह अर्णब के दरवाजे के बाद आपके दरवाजे पर होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं।

इस पूरे प्रकरण में दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी जमात के निशाने पर कांग्रेस है जो महाराष्ट्र में न तो तीन में है और न ही तेरह में। महाराष्ट्र में सरकार उद्धव ठाकरे की है जो शिवसेना से हैं। और गृहमंत्री अनिल देशमुख हैं जो एनसीपी से वास्ता रखते हैं। सरकार में भी कांग्रेस तीसरे पायदान पर ही रहती है। बावजूद इसके पूरा हमला कांग्रेस पर केंद्रित है। यह बात बताती है कि इस मसले पर भी बीजेपी और संघ जमात खुली राजनीति कर रहे हैं।

इस तिलमिलाहट की वजह को समझा जा सकता है। यह संघ-बीजेपी के दिमाग पर हमला हुआ है। अर्णब की यह गिरफ्तारी उसे भविष्य के एक बड़े खतरे का संकेत दे रही है। दरअसल मीडिया में वह जमात जिसके सत्ता के साथ नाभिनाल के रिश्ते हैं और पिछले छह सालों से वह भक्त पत्रकारिता में जुटी हुई थी। इस घटना से उसके डर कर अलग हो जाने का खतरा है। क्योंकि सरकार का चारण और भाट बनकर उसने पहले ही अपनी पत्रकारिता की साख गवां दी है और अब अगर उसका व्यक्तिगत जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो भला वह सत्ता के साथ क्यों रहेगा?

और ऊपर से इस तरह की तमाम कार्रवाइयों की न केवल आशंका बनी रहेगी बल्कि जब भी इस तरह का कोई मौका आएगा तो केंद्र सरकार उसकी रक्षा करने में अक्षम हो जाएगी। इस चीज की महज आशंका ही सरकार के साथ खड़ी मीडिया समर्थकों की व्यवस्था तास के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर जाएगी। और सरकार ने इस खतरे को सूंघ लिया है इसीलिए उसने अर्णब के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिससे वह भले ही अर्णब को न बचा पाए लेकिन इस बात का एहसास ज़रूर करा दे कि इस तरह के किसी भी मौके पर पूरी जमात संबंधित शख्स के साथ खुलकर खड़ी होगी।